भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2157

गुरूवार, 18 दिसंबर, 2025 / 27 अग्रहायण, 1947 (शक)

सगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन

2157. श्री कपिल सिब्बलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ईपीएफओ और ईएसआईसी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 और 2026-26 की पहली छमाही के दौरान संगठित क्षेत्र में कितनी नियमित नौकरियों का सृजन किया गया है;

(ख) क्या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की तिमाही बुलेटिन में 20-29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर में कोई कमी आई है; और

(ग) कौशल भारत मिशन के तहत वर्ष 2025 के दौरान आरंभ किए गए या विस्तृत किए गए कौशल विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): वेतन सूची आँकड़े (पेरोल डेटा) के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ईएसआईसी में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 2,25,87,895 है और वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-25 से सितंबर-25) के दौरान 1,08,28,370 है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के वेतन सूची आँकड़े (पेरोल डेटा) के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में निवल वेतन (पेरोल) अभिदाताओं की संख्या 1,29,78,168 है और वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-25 से जुलाई-25) के दौरान 69,03,006 है।

(ख): 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 के 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है। इसके अलावा, जुलाई-सितंबर 2025 त्रैमासिक बुलेटिन पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सीडब्ल्यूएस (करंट वीकली स्टेटस) आधार पर उसी श्रेणी के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 14.8% थी। मासिक / त्रैमासिक पीएलएफएस अनुपात में बदलाव ज़्यादा बारंबारता और मौसमी बदलावों के कारण से हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक रूप से दीर्घकालिक प्रवृतियों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

जारी....2/-

(ग): वर्ष 2015 में शुरू किए गए भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस भविष्य के लिए तैयार करने में सक्षम बनाना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन और पुन:कौशल के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएस): जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में अशिक्षित, नव-साक्षरों और शिक्षा के प्राथमिक स्तर वाले व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजन और अन्य उचित प्रकरण में आयु में उचित छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): यह योजना अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और अप्रेंटिस को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके अप्रेंटिस की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण के अंतर्गत उद्योग में प्रशिक्षण कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल हैं।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करना हैं।

मंत्रिमंडल द्वारा पांच वर्षों की अवधि में 60,000/- करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय सहित उन्नत आईटीआई (पीएम सेतु) योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार को भी मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए हब (200)-स्पोक (800) मॉडल के माध्यम से 1,000 आईटीआई को अपग्रेड करना है।

*****